the pioneer
New Delhi
Thursday | September 10 | 2009

214

Govt plans to employ more rural populace in NREG

Akhilesh Suman ■ New Delhi

Prime Minister Manmohan Singh is welcomed by Minister of Rural Development & Panchayati Raj CP Joshi during a conference of State Ministers of Rural Development and Panchayati Raj on Rural Employment, in New Delhi on Wednesday PTI

Departing from its conventional stand on the National Rural Employment Guarantee Act, Union Rural Development Minister CP Joshi on Wednesday pleaded for the employment of all those who are 'employable' in rural areas, but have not volunteered under the Ministry's flagship programme. His appeal came in the presence of PM Manmohan Singh and Rural and Panchayati Raj Development Ministers of all the States, at a conference on rural development.

"If more than 12 crore families are living in the countryside and only 14 per cent of those ask for 100 days' work, it forces us to think how can we utilise the potential of those who are not performing manual works to change the rural economy," Joshi told the Rural Development and Panchayati Raj Ministers.

In 2008-09, only 1.87 per cent of total beneficiaries demanded 100 days' work and the Ministry was surprised since in the face of drought, the demand under the NREG should have increased.

Joshi has already allowed small and marginal farmers to work in their fields and get remuneration under NREGS. This was a major shift in the NREGS to move forward practically from the BPL to APL families, who hesitate to work on the field of other farmers but can work on their own assets to increase productivity.

Joshi quoted the PM, who had suggested to him to go ahead with his intentions to enlarge the scope of NREG and converge the programme with agriculture, water and forestry.

Questions had been raised by the farmers in the beginning that due to NREG, there was difficulty in getting agriculture labour and the issue was also raised in Parliament to provide the scheme to farmers in the form of labour subsidy.

Joshi elaborated, "If you want to raise agriculture growth, NREG can be a tool; the question is to which works the NREG could be extended." The vision was obvious and the NREG Act has the provision to decide about the type of work in consultation with the State Governments.

Prime Minister Manmohan Singh also endorsed Joshi's ideas and said, "We would work purposefully ...to achieve the objective of spreading and deepening of rural prosperity and of employment generation."

In his speech, Joshi also directed the State Governments to use the NREG specifically for rainwater harvesting. The meeting consensus had evolved to converge NREG with Livelihood Mission in addition to giving banking facility to the beneficiaries through non-banking institutions or paying the wages on the spot.

The Indian EXPRESS NEW DELHI | THURSDAY | SEPTEMBER 10 | 2009

How women's touch softened the blow in village

CHANDAN HAYGUNDE
SANGLI, SEPTEMBER 9

IT didn't require the intervention of the police or the government to restore normalcy in Kavthepiran village in Sangli, where a Muslim religious place was damaged during the riot. Interestingly, this village, governed by women, had received the central government's 'best village award' in 2006.

The gram panchayat of Kavthepiran village, which is run by women, has decided to repair the damaged Muslim religious places and try to get life back to normal. The women have a major say, as not many houses here are owned by men.

"Our Muslim sisters played an equal role in getting the award for our village. There are over 100 Muslim houses in the village and some had started leaving the village after the riots. But we stopped them. All women from the village visited the Muslim houses and assured to protect them. The gram panchayat has decided to repair the damaged masjid as well," said the village sarpanch Nita Bhosale.

Wrestler Bhimrao Mane, former sarpanch, who played a major role in getting the award for Kavthepiran, said, "I was shocked to see riots in my village. Someone circulated CDs of Miraj riots in our village. Apparently there was news of some Muslims forcing a Hindu girl to consume poison at Manerajouri. This spread anger among some youths who launched an attack on Muslims. I was away and rushed to the village on knowing about it. But the damage was done," said Mane. "District superintendent Krishna Prakash came to our village with a huge force but we asked him to leave. We wanted to settle the matter on our own," he added.

"What has happened is the past. Hindus have been inviting us during all their festivals for many years. We panicked during the riot. But we still have faith in our Hindu neighbours, said Shabbir Pathan, one of those who never thought of leaving the village.

"We don't believe in police at all. When the riots broke out, we had turned to our Hindu friends for help," said Sikandar Indamdar, another villager.

राष्ट्रीय सहारा = नई दिल्ली । मंगलवार • 22 सितम्बर • 2009

पंचायती राज की सफलता के लिए

मुद्दा

भारत डोगरा

आज भी पंचायतों को यही शिकायत है कि हकीकत में उन तक बहुत कम विभागों व कार्यों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। जो थोड़ा-बहुत कार्यक्षेत्र उन्हें मिला है उसमें भी सरकारी अधिकारियों को कमीशन दिये बिना कार्य नहीं करवाये जा सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी प्रायः प्रधान को दबदबे में रखने का प्रयत्न करते हैं। कमजोर ग्राम प्रधान के लिए नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर निकलना और कठिन हो जाता है। इनसे कई बार सेक्रेटरी अनुचित कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर मनमानी करते हैं।

पंचायती राज की मुख्य समस्या भ्रष्ट नौकरशाही की ओर से है जो पंचायतों को न पूरे अधिकार प्राप्त करने देती है और न ईमानदारी से कार्य करने देती है। पर पंचायती राज का दूसरा दृष्टिकोण पंचायतों और उनके प्रधानों के अपने भ्रष्टाचार की ओर भी ध्यान दिलाता है। इसके पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं कि नाममात्र का मानदेय पाने वाले अनेक प्रधान कैसे कम समय में मालदार हो जाते हैं। विशेषकर दबंग व्यक्ति प्रधान बनकर पद का दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि ऐसे उम्मीदवार प्रधान पद के चुनाव में भी लाखों खर्च करने को तैयार रहते हैं। सीट आरक्षित होने पर प्रायः ऐसे व्यक्ति किसी उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं जो पूरी तरह उनके दबदबे में रहे।

व्यवहार में भ्रष्ट अधिकारियों व स्थानीय दबंगों की सांठ-गांठ से ही भ्रष्टाचार फलता-फूलता है और ईमानदार प्रधानों को भी धीरे-धीरे समझ आ जाता है कि बिना कमीशन दिये काम करवाना कितना कठिन कार्य है। सामान्यतः अधिकांश सरकारें, नेता व अधिकारी विकास कार्यों व विभागों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और विकास कार्य सही अर्थों में पंचायती राज को सौंपना नहीं चाहते। किसी तरह यह संभव हो भी जाए तो भी खतरा रहेगा कि पंचायतों पर कब्जा करने वाले दबंग विकास-राशि का बड़ा हिस्सा स्वयं हड़प लेंगे या बांट लेंगे।

विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय का कहना है, 'मुख्य मुद्दा आम लोगों के सशक्तीकरण का है। पंचायत स्वयं शक्ति का केन्द्र बन सकती है, अतः लोगों तक वास्तविक शक्ति पहुंचाना उद्देश्य होना चाहिए।' वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता गया प्रसाद गोपाल कहते हैं, 'पंचायतों के सशक्तीकरण के साथ गरीब कमजोर परिवारों के सशक्तीकरण और उनकी एकता मजबूत करने की जरूरत है।' सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे कहते हैं, 'ग्रामसभा को सशक्त करना, पारदर्शिता की मजबूत व्यवस्था बनाना, कमजोर तबकों व महिलाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है।' इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू कहते हैं, 'जब भी कमजोर या ईमानदार व जुझारू प्रधान या अन्य निर्वाचित सदस्य संकट में पड़ें तो उनकी सहायता के लिए व्यापक प्रयास अवश्य होने चाहिए।'

मतलब विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब गांव के भीतर लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके लिए ग्रामसभा यानी गांव के सभी वयस्कों की आम सभा की नियमित बैठकें सही ढंग से होनी चाहिए। सभी को, विशेषकर कमजोर तबकों व महिलाओं को विचार प्रकट करने के अवसर मिलने चाहिए। गांव में कमजोर आर्थिक-सामाजिक परिवारों के संगठन बनने चाहिए। महिला-मंडलों का गठन होना चाहिए। वार्ड सदस्यों की आवाज को महत्व मिलना चाहिए व वार्ड सभाओं की भी नियमित मीटिंग होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियों जैसे निर्माण, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सक्रियता बनी रहनी चाहिए। किसी के द्वारा सूचना मांगने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अधिकांश जरूरी हिसाब-किताब सार्वजनिक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न विकास कार्यों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। ग्राम-प्रधान व वार्ड सदस्यों को उनके खर्चों, यात्राओं, कार्य आदि के अनुकूल मानदेय व भत्ते मिलने चाहिए ताकि कम से कम जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यह संभव हो। अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रधानों व अन्य निर्वाचित सदस्यों को अपना कार्य भली-भांति चलाने के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं व कमजोर तबकों को चुनावों में कोई जोर-जबरदस्ती या दहशत न सहनी पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। चुनाव सद्भावना के माहौल में हों व उसके कारण गांव में दुश्मनियां न बढ़ें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। विकास कार्यों के नियोजन व अन्य कार्यों में विपक्षी उम्मीदवारों व अन्य अनुभवी गांववासियों को भी शामिल करना चाहिए।